

## नई आर्थिक नीति (New Economic Policy)

पी. वी. नरसिंह राव सरकार ने जून 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को नयी दिशा प्रदान की थी। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी मॉडल) के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गयी थी। इस नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी, जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। इस नई आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भुगतान संतुलन (BOP) का निरंतर नकारात्मक होना था।

नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिये 1991 में अपनाई गई आर्थिक नीतियों से है। अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधारों के लिये स्थिरीकरण उपायों को अपनाया गया था।

### नई आर्थिक नीति (New Economic Policy)

1990 के दशक में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए अपने पिछले आर्थिक नीतियों से विचलित और निजीकरण की दिशा में शुरुआत करने का फैसला किया और अपनी नई आर्थिक नीतियों को एक के बाद एक घोषित करना शुरू कर दिया। आगे चलकर इन नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिले और भारत के आर्थिक इतिहास में ये नीतियाँ बहुत उपयोगी साबित हुईं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव थे और वित्तमंत्री मनमोहन सिंह थे।

1990 के दशक के पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नयी आर्थिक नीति को अपनाने लिए मजबूर कर दिया था। आर्थिक संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया सके।

### नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) : प्रमुख घटक

नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख घटक थे- उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण।

#### उदारीकरण

उदारीकरण 1991 भारतीय कंपनियों में निम्नलिखित तरीके से उदारीकरण से पहले उद्योगों पर डाल दिया गया है, जो लाइसेंस, कोटा और कई और अधिक प्रतिबंध और नियंत्रण का अंत करने के लिए है-

कुछ को छोड़कर लाइसेंस का उन्मूलन।

व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार या संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं।

कीमतें तय करने में स्वतंत्रता।

आयात और निर्यात में उदारीकरण।

माल और सेवाओं के आंदोलन में स्वतंत्रता

माल और सेवा की कीमतें तय करने में स्वतंत्रता

### निजीकरण

निजीकरण निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका देने और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने के लिए संदर्भित करता है। निजीकरण सरकार की नीति पर अमल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए -

सार्वजनिक क्षेत्र , यानी, निजी क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के हस्तांतरण का विनिवेश

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर ) के बोर्ड की स्थापना करना। इस बोर्ड नुकसान पीड़ित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए स्थापित किया गया था।

सरकार की हिस्सेदारी के कमजोर पड़ने। विनिवेश के लिए निजी क्षेत्र की प्रक्रिया में 51% से अधिक शेयरों का अधिग्रहण तो यह निजी क्षेत्र के लिए स्वामित्व और प्रबंधन के हस्तांतरण में यह परिणाम है।

### वैश्वीकरण

यह दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के लिए संदर्भित करता है। 1991 तक भारत सरकार ने आयात और आदि का आयात टैरिफ , प्रतिबंध के लाइसेंस के लिए, लेकिन नई नीति सरकार निम्नलिखित उपायों के द्वारा वैश्वीकरण की नीति अपनाई के बाद इस संबंध में विदेशी निवेश के संबंध में सख्त नीति का पालन किया गया था-

आयात उदारीकरण। सरकार पूंजीगत वस्तुओं के आयात से कई प्रतिबंध हटा दिया।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा बदल दिया गया (फेमा)

टैरिफ संरचना का युक्तिकरण

निर्यात शुल्क के उन्मूलन।

आयात शुल्क में कमी।



## नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) : मुख्य उद्देश्य

वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति आरम्भ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य थे, वे निम्नलिखित हैं

भारतीय अर्थव्यवस्था को 'वैश्वीकरण' के मैदान में उतारने के साथ-साथ इसे बाजार के रूख के अनुरूप बनाना।

मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना।

आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना।

आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ-साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। अर्थव्यवस्था के लिए बाजार अनुरूप एक आर्थिक परिवर्तन लाना।

प्रतिबंधों को हटाकर, माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अन्तरराष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना।

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना। इसी कारण सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या घटाकर 3 कर दिया गया।

## नयी आर्थिक नीति (New Economic Policy) : विशेषताएं

लाइसेंस - केवल छह उद्योगों लाइसेंस योजना के तहत रखा गया था।

निजी क्षेत्र के लिए प्रवेश - सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका केवल चार उद्योगों तक ही सीमित था ; बाकी सभी उद्योगों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए थे।

विनिवेश - विनिवेश कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बाहर किया गया था।

विदेश नीति के उदारीकरण - विदेशी इक्विटी की सीमा कई गतिविधियों में 100 % करने के लिए उठाया गया था , यानी, एनआरआई और विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी गई।

तकनीकी क्षेत्र में उदारीकरण - स्वतः अनुमति विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय कंपनियों को दिया गया था।



विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्थापना करना - इस बोर्ड को बढ़ावा देने और भारत में विदेशी निवेश लाने के लिए स्थापित किया गया था।

लघु उद्योग की स्थापना करना।

